



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2001/भाद्र 9, 1923

No. 237]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2001/BHADRA 9, 1923

शाणिन्य एवं उद्योग मंत्रालय

(बाणिन्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2001

सं. 34 (आर ई-2001)/1997—2002

फा. सं. 01/94/180/051/ए एम.02/पी सी 4.—का. आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-3-1997 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में यथाअधिसूचित नियर्त और आयात नीति के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1), (आर ई 01), 1997—2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1) पैराग्राफ 7.28 क(ii) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

“यदि नियर्त दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया गया है लेकिन मूल्य के अनुसार कमी है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि उस लाइसेंस विशेष के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोजन (या सकारात्मक मूल्य संयोजन जैसा भी मामला हो) प्राप्त कर लिया गया हो। (यदि लगाया गया वास्तविक मूल्य संयोजन न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोजन से कम है तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा अगर लगाया गया वास्तविक मूल्य संयोजन प्राप्त कर लिया गया हो)

तथापि, यदि नियर्तक आवश्यक न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोजन (अथवा सकारात्मक मूल्य संयोजन, जैसा भी मामला हो) प्राप्त नहीं कर पाता तो, उसे “लेखा शीर्ष : 0037 सीमा शुल्क और लघु शीर्ष : 101 - आयात” को दर्शाती हुई सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की प्राधिकृत शाखा में टी आर के माध्यम से बराबर राशि जमा करवानी होगी ताकि जमा करवाई गई राशि और भारतीय रूपयों में वसूल किया गया पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य दोनों मिल कर लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य से अधिक न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोजन (अथवा सकारात्मक मूल्य संयोजन, जैसा भी मामला हो) का लेखा-जोखा देंगे।”

- 2) द्वितीय पैराग्राफ 7.28 ख(ii) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
 “तथापि, यदि वह न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोजन प्राप्त नहीं कर पाता तो, उसे “लेखा शीर्ष : 0037 सीमा शुल्क और लघु शीर्ष : 101 - आयात” को दर्शाती हुई सैन्ड्रल बैंक ऑफ इण्डिया की प्राधिकृत शाखा में टी आर के माध्यम से बराबर राशि जमा करवानी होगी ताकि जमा करवाई गई राशि और भारतीय रूपयों में वसूल किया गया पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य दोनों मिल कर लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य से अधिक न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोजन का लेखा-जोखा देंगे।”
- 3) पैराग्राफ 7.29 के प्रथम वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :-
 “बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता (जैसा भी मामला हो) के विनियमन या लागू करने के कारण लाइसेंसधारक से प्राप्त होने वाले ब्याज सहित सीमा शुल्क, लाइसेंसधारक को लाइसेंसिंग/सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा माँगे जाने पर 30 दिनों के भीतर निर्धारित टी आर चालान में संबंधित सीमाशुल्क राजस्व शीर्ष यानी मुख्य शीर्ष : 0037-सीमाशुल्क और लघु शीर्ष : 101 - आयात शुल्क को जमा कराना होगा तथा लाइसेंसिंग सीमाशुल्क प्राधिकारी को तुरंत इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।”
- 4) “पूँजीगत माल का आयात” से संबंधित पैरा 9.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-
 “ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों के मामले में, पुराने पूँजीगत माल सहित पूँजीगत माल का आयात विधिक वचनबद्धता के अनुसार किया जाएगा।”
- 5) पैरा 9.29 क(ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
 “निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन या सुपर स्टार व्यापार सदन स्तर का दर्जा देने के लिए ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को डी टी ए में इसकी मूल कम्पनी के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के साथ जोड़ा जाएगा।”
- 6) पैरा 9.29 क(घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रस्तिस्थापित किया गया है :-
 “ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों को विनिर्माण क्षेत्र में 100% एफ डी आई अनुमत है। सेवाओं और व्यापार क्षेत्र में ई डी आई के लिए, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा यथाअधिसूचित क्षेत्रीय मानदण्ड लागू होंगे।”
- 7) पैरा 9.30(ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
 “परिशिष्ट - 41 के अन्तर्गत न आने वाली मर्दों के संबंध में, विकास आयुक्त शुल्क मुक्त योजना के तहत अधिसूचित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए वेस्टेज निश्चित करेंगे। इन दो के अन्तर्गत न आने वाली मर्दों के लिए, विकास आयुक्त, यदि आवश्यक समझें, तो निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड को प्रस्ताव भेज सकते हैं।
 जिन मामलों में, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के भीतर विकास आयुक्त द्वारा वेस्टेज मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, उन्हें विलम्ब के कारणों सहित सूचना के लिए अनुमोदन बोर्ड को भेजा जाएगा।”
- 8) प्रारम्भिक पैरा 9.37 ख) (6) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :-
 “स्थापना स्थल/विस्तार में परिवर्तन : एल ओ पी/एल ओ आई में उल्लिखित स्थापना स्थल से अन्य किसी स्थापना स्थल के परिवर्तन और/या अतिरिक्त स्थापना स्थल को शामिल करने की अनुमति देना बशर्ते कि : ”

- 9) पैरा 9.37 ख) (10) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :-
 “दो अथवा अधिक ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटों का विलय : दो या अधिक यूनिटों को एक यूनिट में मिलने की अनुमति देना बशर्ते कि यूनिट उसी विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार के भीतर हो”
- 10) पैरा 9.37 ख) (11) को हटा दिया गया है ।
- 11) पैराग्राफ 9-क, 4, में, अन्तिम उप पैरा का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :-
 “निवल विदेशी मुद्रा के वार्षिक परिकलन के लिए, आयातित पूँजीगत माल के मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी फीस के एक मुश्त भुगतान को निम्नानुसार परिशोधित किया जाएगा ।”
- 12) पैराग्राफ 9 - क 8 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :—
 “एस ई जैड यूनिटें स्व प्रमाणीकरण आधार पर लागू शुल्क के भुगतान पर डी टी ए में उत्पादों और सेवाओं सहित माल को बेच सकती है ।”
- 13) पैराग्राफ 9 - क 11 (4) में अन्तिम वाक्य को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-
 “सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय मानदण्ड सेवाओं और व्यापार संबंधी क्रिया कलापों में विदेशी निवेश पर भी लागू होंगे ।”
- 14) पैराग्राफ 9 - क 12 में, निम्नलिखित नए उप-पैरा (घ) को शामिल किया गया है :-
 “(घ) एस ई जैड यूनिटों को उप-ठेकेदार के परिसरों से मोल्ड्स, जिग्स, टूल्स, फिकर्चर्स, टैक्लस, इन्स्ट्रूमेन्ट्स, हैनार्स और पैटेन्स और ड्राइन्स को हटाने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि ये जॉब वर्क पूरा होने पर एस ई जैड यूनिटों के बाण्डेड परिसर पर निर्धारित अवधि के भीतर वापिस लाए जाएँगे ।”
- 15) पैराग्राफ 9 - क 19 (3) (ख) को हटा दिया गया है ।
- 16) पैरा 9 - क 19(3) में निम्नलिखित दो नए उप-पैरा (छ) और (ज) जोड़े गए है :-
 “(छ) सेवा क्षेत्र (सॉफ्टवेयर और आई टी एनेबल्ड सेवाएँ, ट्रेडिंग या ऐसी ही कोई अन्य सेवा गतिविधि जो बी ओ ए द्वारा नामित की जाए) में यूनिटों को स्थापित करने के अलावा एस ई जैड यूनिटों को स्थापित करने के लिए अनुमत आवेदन पत्र बशर्ते कि मद के विर्तिमाण हेतु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत न पड़े ।
 (ज) विधिक प्रतिबद्धता को निष्पादित करने पर संबंधित विकास आयुक्त द्वारा एस ई जैड यूनिटों को अपने आप ही ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा ।”
- 17) पैरा 10.3 को निम्न रूप से संशोधित किया गया है :
 “नीति के पैरा 10.2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत ई ओ यू/ई पी जैड/एस ई जैड/ई एच टी पी/एस टी पी को वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 10.3 (क) (ख) और (ग) के अंतर्गत लाभों का पात्र होगा ।”
- 18) पैरा 10.7 में एक अंतिम उप-पैरा निम्न प्रकार से जोड़ा गया है :
 “पैरा 10.2(ख) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटों को टर्मिनल एक्साईज ऊटी के भुगतान का प्रमाण पेश करने तथा डी टी एक सप्लायर से डिस्क्लेमर प्रमाण पत्र, पेश करने पर टर्मिनल एक्साईज ऊटी शुल्क वापसी की पात्र होंगी ।”

- 19) परिशिष्ट 16 खखख के अनुलग्नक को इस सार्वजनिक सूचना के संबंधित संलग्नक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- 20) परिशिष्ट 16 ड. और उसके अनुलग्नक 1 को इस सार्वजनिक सूचना के संबंधित परिशिष्ट तथा संलग्नक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- 21) परिशिष्ट 16 च और ज को इस सार्वजनिक सूचना के संबंधित संलग्नक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- 22) परिशिष्ट 16 और 16 ट हटा दिए गए हैं ।
- 23) इस सार्वजनिक सूचना के संबंधित संलग्नक के रूप में परिशिष्ट 16 ठ जोड़ दिया गया है ।
- 24) इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के अनुसार परिशिष्ट 26 को जोड़ा जाता है ।
- 25) परिशिष्ट 28 क में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियाँ की गई हैं :-

(क) उत्पाद समूह: इंजीनियरिंग (उत्पाद कोड 61)

(i) निम्नलिखित प्रविष्टि को इस प्रकार संशोधित किया गया है :

क्रम संख्या	निर्यात उत्पाद का विवरण	डी ई पी बी दर	वैल्यू कैप
229	स्टील पैगस	13.00	40 रु./किग्रा.

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टियाँ निमानुसार संशोधित की गई हैं :

क्रम सं0	निर्यात उत्पाद का विवरण	डी ई पी बी दर	वैल्यू कैप
93.	2" गैल्वानाइज्ड/जिंक कोटेड बनस	14.00	95/रु0 कि.ग्रा.
94.	2" गैल्वानाइज्ड/जिंक कोटेड फ्लेन्ज	14.00	90/रु0 कि.ग्रा.
96.	रबड़ गास्केट सहित 3/4" गैल्वानाइज्ड बनस	14.00	96/रु0 कि.ग्रा.
98.	3/4" गैल्वानाइज्ड/जिंक कोटेड बनस	14.00	140/रु0 कि.ग्रा.
99.	3/4" गैल्वानाइज्ड/जिंक कोटेड फ्लेन्ज	14.00	100/रु0 कि.ग्रा.
227	स्टील क्लैम्प (गैल्वानाइज्ड और अन्नैल्वानाइज्ड)	15.00	70/रु0 कि.ग्रा.
438.	वॉशर/गास्केट सहित अथवा रहित 2" बनस	14.00	88/रु0 कि.ग्रा.

(ख) उत्पाद समूह : रसायन (उत्पाद कोड ; 62)

(1) निम्नलिखित प्रविष्टि निमानुसार संशोधित की जाती है :

क्रम सं0	निर्यात उत्पाद का विवरण	डी ई पी बी दर	वैल्यू कैप
777	पोटाशियम पैन्सलीन - जी फर्स्ट क्रिस्टल/पैन्सलीन पोटाशियम फर्स्ट क्रिस्टल/ बी पी/यू एस पी/आई एस पी	16.00	600/रु0 बी ओ यू

(ग) उत्पाद समूह : इलैक्ट्रॉनिक्स (उत्पाद कोड ; 83)

(2) निम्नलिखित प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित की जाती है :

क्रम सं0	निर्यात उत्पाद का विवरण	डी ई पी बी दर	वैल्यू कैप
43	टेलिविज़न - सभी स्क्रीन आकारों के रंग उनके सी के डी/एस के डी/सी बी यू में प्रोजैक्शन टी बी और वीडियो प्रोजैक्टर सहित	22.00	(i) 17" तक और सहित आकार के लिए 4200 रु प्रति नग/ (ii) 17" से अधिक आकार (17" छोड़कर) के लिए 8700 रु प्रति नग

26. परिशिष्ट 32क के क्रम सं0 12 और परिशिष्ट 32ख के अन्तर्गत सूची क की क्रम सं0 12 पर दिए गए मैसर्ज अमेरिकन क्वालिटी असैसर्ज (इण्डिया) प्रा.लि. (ए क्यू ए, यू एस ए के कार्यालयों के अधीन) का पता और फोन न. निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं :-

3-6-157, विक्टरी विहार, चतुर्थ तल, हिमायत नगर, हैदराबाद - 500029

दूरभाष : 040 - 3222894, 3222895

फैक्स : 040 - 3223023

ई मेल : aqa@aqa-india.com/srihari2hd1.vsnl.net.in

27) परिशिष्ट 41 के सन्दर्भ में निम्नलिखित संशोधन जारी किया जाता है जो कि “ई ओ यू और ई पी जैड में यूनिटों के लिए स्क्रैप/वेस्ट मेट्रीरियल के मानदण्ड से सम्बन्धित है।

नीचे दी गई तालिखा के अनुसार प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-41 के क्रम सं0 100 पर काम्बड कॉटन यार्न के लिए वेस्टेज मानदण्ड 01.12.1999 से लागे होंगे जो कि सार्वजनिक सूचना सं0 42(आर ई99) के जारी करने की तारीख है:

क्रम सं0	विनिर्मित माल	प्रयोग किया गया आयातित माल	आयातित माल पर स्क्रैप या वेस्ट का प्रतिशत
100	क) 40' से कम कॉटन यार्न ख) 41 और इससे अधिक काम्बड कॉटन यार्न	कॉटन कॉटन	25 प्रतिशत 30 प्रतिशत

28) परिशिष्ट 43 इस सार्वजनिक सूचना के रेलिवेट संलग्नक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

29) राज्य प्रमुख दिल्ली के अधीन “मूल प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची-गैर वरीयता” से सम्बन्धित परिशिष्ट-51 ख में निम्नलिखित जोड़ा जाता है।

दिल्ली

8. मै0 लघु उद्योग भारती

1 ई/11, रामतीर्थ नगर, झण्डेवाला एक्सटेन्शन

नई दिल्ली - 110055

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

परिशिष्ट खखख का अनुलग्नक

विशेष आर्थिक जौन यूनिटों की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट

भाग - क

1. एकक का नाम
 2. एल ओ पी सं० एवं तारीख
 3. विनिर्माण की मद
 4. वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ
करने की तारीख
 5. पूँजीगत माल का आदि शेष
 6. वर्ष के दौरान पूँजीगत माल का आयात
 7. वर्ष के दौरान अन्तर एकक हस्तांरण
के अधीन प्राप्त पूँजीगत माल
 8. तकनीकी फीस के मद्द विदेशी मुद्रा
की निकासी
- रुपये लाखों में 000 अमरीकी डालरों में

योग:

9. वर्ष के आरम्भ मे आयातित कच्चे माल,
उपभोज्यों, अतिरिक्त कलपुर्जों आदि का
अथ शेष
10. वर्ष के दौरान अयातित कच्चा माल,
उपभोज्य, अतिरिक्त कलपुर्जे आदि

11. अन्तर एकक हस्तांतरण के अधीन
अन्य एककों को हस्तांतरित कच्चा
माल, उपभोज्य, अतिरिक्त कलपुर्जे
12. अन्तर एकक हस्तांतरण के अधीन प्राप्त
कच्चा माल, उपभोज्य, अतिरिक्त कलपुर्जे
13. वर्ष के दौरान उपभोग किया गया आयातित
कच्चा माल, उपभोज्य, अतिरिक्त कलपुर्जे
14. वर्ष के अंत में आयातित कच्चे माल, उपभोज्यों,
अतिरिक्त कलपुर्जों आदि का अन्त शेष
15. ई.सी.बी. पर ब्याज, निर्यात कमीशन, विदेशी
यात्रा, रायल्टी/लाभांश का भुगतान आदि के
मद्दे विदेशी मुद्रा की निकासी

योग:-

16. निर्यात का पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य
17. पेराग्राफ 9.10 के अन्तर्गत की गई आपूर्तियाँ

योग:-

18. टी ए बिक्री
 - (1) तैयार माल
 - (2) अस्वीकृत माल
 - (3) अवशिष्ट और
19. अर्जित वास्तविक निवल विदेशी मुद्रा

20. वास्तव में प्राप्त किया गया निर्यात निष्पादन

भाग-ख (31.3.2001 के अनुसार)

अधिकृत पूँजी

प्रदत्त पूँजी

सीधा विदेशी निवेश

1. अनुमोदित

(प्रारम्भ से)

2. वास्तविक अतः प्रवाह

एन. आर. पूँजी

1. अनुमोदित

(प्रारम्भ से)

2. वास्तविक अतः प्रवाह

भारतीय इकिवटी

रोजगार:

पर्वेक्षीय

गैर पर्वेक्षीय

योगः

पुरुष

महिला

योगः

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अनुमति पत्र के लिए उपर्युक्त सूचना पृथक दी जाए।
2. आंकड़े वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च के अनुरूप होने चाहिए।
3. फार्मेट में दी गई सूचना प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अधिप्रमाणित की जाए और यूनिट द्वारा रखे गए रिकार्ड और रजिस्टरों के लेखा के संदर्भ में किसी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा उनका सही होना प्रमाणित किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट - 16 ड.

ई ओ यू/ई पी जैड/एस ई जैड यूनिटों के निष्पादन की निगरानी हेतु दिशा निर्देश

1. गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के अंत से पूर्व विकास आयुक्त द्वारा प्रत्येक कार्यरत यूनिट एवं अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के बारे में वार्षिक समीक्षा की जाएगी।
2. प्रत्येक वर्ष 30 जून तक नीचे दिए तीन प्रपत्रों में प्रत्येक विकास आयुक्त द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को वार्षिक निष्पादन समीक्षा का सारांश भेजा जाएगा।

प्रपत्र-1 गत वर्ष की तुलना में निष्पादन और मानिटरिंग का तुलनात्मक विवरण।

प्रपत्र-2 ई ओ यू/ई पी जैड/एस ई जैड यूनिटों के वार्षिक निष्पादन का सारांश, सैक्टरल उपयोग सहित सैक्टर-वार

प्रपत्र-3 समीक्षा का परिणाम दर्शाते हुए एन एफ ई एवं एन एफ ई पी संबंधी यूनिट वार विवरण।

- (क) ई ओ यू/ई पी जैड एकक:
वार्षिक निगरानी के लिए मानदण्ड
- (1) निगरानी - प्रथम और द्वितीय वर्ष के अन्त में यदि प्राप्त किए गए एन एफ ई पी और/या निर्यात निष्पादन (परिशिष्ट-1 में दिए गए मानदण्ड के अनुसार) में कमी है,
 - (2) दांडिक कार्रवाई: यदि तीसरे वर्ष के अन्त में या परवर्ती वर्ष में एन एफ ई पी/ई पी एकिजम नीति के परिशिष्ट-1 के अनुसार प्राप्त नहीं किया गया है। यूनिट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यूनिट के उत्तर को देखने के बाद यदि यह नोट किया जाता है कि यूनिट ने नीति के अनुसार एन एफ ई पी/ई पी प्राप्त नहीं किया है तो विकास आयुक्त विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत कार्रवाई करेगा।
 - (3) यदि किसी विशेष वर्ष में एन एफ ई पी/ई पी में कमी के कारण यूनिट के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है और आगामी वर्षों में भी वह उसी श्रेणी में आता है तो यूनिट के विरुद्ध नई दण्डात्मक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। तथापि, कानूनी कार्रवाई के दौरान यदि यह पता चलता है कि एकक के निष्पादन में सुधार हुआ है और वह अब नीति के अनुसार एन एफ ई पी/ई पी को पूरा कर रहा है तो संबंधित विकास अधिकारी कोई निर्णय लेने से पहले इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है।

निगरानी की पद्धति

1. डिबालिंग के सभी मामलों में जिनमें यूनिट ने निविष्टि आयात कर ली है तथा एन एफ ई पी/ई पी के मामले में अनुमोदन पत्र की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो यूनिटों को कारण बताओ नोटिस जारी करके उनके विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जानी चाहिए। जो एक वर्ष या अधिक अवधि से कार्यरत नहीं है तो उन यूनिटों के विरुद्ध एल ओ पी/एल ओ ए को निरस्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए।
2. समय-समय से निर्यात आयात नीति के परिशिष्ट-1 में दिए विभिन्न सैकटरों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम निर्यात निष्पादन जो कि' न्यूनतम निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क भूल्य अनुसार होगा।
3. निर्यात आयात नीति के पैरा 9.29 के अनुसार एन एफ ई पी की गणना की जाएगी। एकरूपता की दृष्टि से परिशिष्ट-1 में दी गई एन एफ ई पी की गणना के दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा। और
4. जिन यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से एक वर्ष पूरा नहीं किया है उनकी निगरानी नहीं की जाएगी। पुरानी यूनिटों के मामले में जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है वार्षिक निगरानी सामूहिक रूप से गत 5 वर्ष के लिए की जाएगी। यदि किसी यूनिट ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से 5 वर्ष से कम का समय पूरा कर लिया है तो उसकी निगरानी पूरे किए गए वर्षों के आधार पर की जाएगी।
5. ई ओ यू/ई पी जेड यूनिटों की समर्वती संयुक्त निगरानी:
 - (क) ई ओ यू/ई पी जेड यूनिटों के निष्पादन की संयुक्त समीक्षा ई पी जेड के विकास आयुक्त और संबंधित सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा छमाही आधार पर की जाएगी अर्थात् ई ओ यू द्वारा दी गई क्यू पी आर के आधार पर गत तिमाही में पूरा होने वाले प्रत्येक वर्ष में अप्रैल-सितम्बर के लिए और गत तिमाही में पूरा होने वाले ए पी आर के आधार पर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए/क्यू पी आर/ए पी आर के प्रणत्र विधिक वचनबद्धता के परिशिष्ट ख और परिशिष्ट खख में दिए गए हैं।
 - (ख) ई ओ यू के ई पी/एन एफ ई पी की संयुक्त समीक्षा विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त और सीमा-शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा की जाएगी जिसमें यूनिट के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा। इससे उन्हें योजना को समझने और परिचालन के संबंध में शंकाओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। विकास आयुक्त को सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्तों की संख्या का पता लगाने जहां बैठकें आयोजित की जाएंगी और

प्रत्येक स्थान का दौरा करने के लिए कार्यक्रम बनाने की सलाह दी जाती है। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक महीने दो स्थानों का दौरा किया जाए ताकि तीन महीने के भीतर सभी स्थानों का दौरा किया जा सके। कुछ स्थानों का दौरा संयुक्त विकास आयुक्त करेंगे और अगले छः महीनों में इन स्थानों को संयुक्त विकास आयुक्त और विकास आयुक्त के बीच बदला जा सकता है। ई पी जेड/एस ई जेड यूनिट के लिए यह समीक्षा स्वयं जोन द्वारा की जाएगी।

(ग) इस योजना का प्रचार करने के लिए ऐसी बैठकों की तारीख से पहले स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिया जाना चाहिए। विकास कार्यक्रम स्थानीय उद्योग और किसी अन्य संगठन जिसकी उस क्षेत्र में प्रतिष्ठा हो, की ऐसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है।

(घ) मौजूदा प्रत्येक यूनिट की समस्याओं को समझने और इनका सम्भव समाधान करने के लिए विस्तृत समीक्षा की जाएगी। निष्पादन में कमी/खराब निष्पादन के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए और अडचनों को दूर करने के लिए यूनिट-वार कार्य-योजना बनाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यूनिट की एक निर्यात संवर्धन नीति और अगले कुछ वर्षों के लिए अनन्तिम लक्ष्य होना चाहिए ताकि इस बात का अंदाजा हो सके कि उसे किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस योजना के किसी दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए चूककर्ता यूनिटों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ङ.) कार्यान्वयनाधीन यूनिटों के लिए अलग से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(च) ऐसे स्थानों पर, यदि बुनियादी सुविधाओं में कमी देखी जाती है तो जिला प्रशासन को परियोजनाएं तैयार करने की सलाह दी जाती है, जिन्हें सी आई बी योजना के तहत अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के माध्यम से मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

(छ) संयुक्त समीक्षा के आधार पर संबंधित विकास आयुक्त वाणिज्य विभाग और सी बी ई सी की सूचना के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और सुधारात्मक उपाय सुझाएगा ताकि चूककर्ता यूनिट निर्यात और आयात नीति/समीशुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार अपना दायित्व पूरा कर सके।

(ख) एस ई जेड यूनिट:

तिमाही और वार्षिक निगरानी

- 1) एस ई जेड यूनिटों के कार्य-निष्पादन की निगरानी निर्यात और आयात नीति के पेरा 9क-5 के अनुसार की जाएगी।
- 2) एस ई जेड यूनिटों के कार्य-निष्पादन की परिशिष्ट 16 ज में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक तिमाही में निगरानी की जाएगी।
- 3) वार्षिक निगरानी परिशिष्ट 16-खखख के अनुलग्नक में निर्दिष्ट ए पी आर के आधार पर की जाएगी। तथापि, दंडात्मक कार्रवाई केवल तभी की जाएगी यदि तीसरे वर्ष के अंत में या बाद के वर्षों में एन एफ ई नकारात्मक है। एस ई जेड योजना में परिवर्तित मौजूदा ई पी जेड यूनिटों के मामले में, ई पी जेड योजना के तहत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख निगरानी के प्रयोजन के लिए यूनिट द्वारा पूरे किए गए वर्षों की संख्या को गिनने की तारीख होगी।
- (4) संयुक्त समीक्षा के दौरान, कमी/खराब निष्पादन हेतु कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जाएं तथा ऐसी समीक्षा के माध्यम से रुकावटों को दूर करने हेतु यूनिट-वार कार्य योजना तैयार की जाए।
- (5) संयुक्त समीक्षा के आधार पर, संबंधित विकास आयुक्त वाणिज्य विभाग और सी बी ई सी की सूचना हेतु रिपोर्ट तैयार करेगा तथा एग्जिम नीति/सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार चूककर्ता यूनिटों को अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाएगा।

ग) अन्य शर्तें

विकास आयुक्त, भारतीय रिजर्व बैंक की परिपत्र संख्या- सी ओ ई एक्स डी 3109/05. 62.05/99-2000 दिनांक 21.2.2000 द्वारा इस विषय में जारी अनुदेशों के अनुसार संबंधित महाप्रबंधक से समन्वय करके ई ओ यू/ई पी जेड/एस ई जेड की विदेशी मुद्रा वसूली/वापसी को मानीटर करेगा।

अनुलग्नक - 1

एन एफ ई पी/एन एफ ई का परिकलन

प्राप्त किए गए एन एफ ई पी/ई पी का परिकलन करते समय निम्नलिखित मूल संघटकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

- i) पूँजीगत माल का परिशोधित मूल्य और तकनीकी जानकारी की फीस
- ii) कच्चे माल के आयात का मूल्य (जिसका वर्ष के दौरान उपभोग किया जाता है और उपभोज्य, अतिरक्त पुर्ज आदि)
- iii) रायल्टी, विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर ब्याज इत्यादि के रूप में विदेशी मुद्रा की अन्य निकासी
- iv) नीति के पेरा 9.10 और 9 के 10 के अधीन की गई डी टी ए बिक्री को छोड़कर लेकिन आपूर्तियों सहित प्रभावित वास्तविक निर्यात का मूल्य

1. पूँजीगत माल का परिशोधित मूल्य :

इस उद्देश्य हेतु पूँजीगत माल का उतना ही मूल्य माना जाएगा जितना कि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के एन एफ ई पी हेतु पेरा 9.40 में और एन एफ ई हेतु 9 के 32 में उल्लिखित है। एन एफ ई पी/एन एफ ई के परियोजन हेतु 5 वर्ष की अवधि से पूर्व आयात किए पूँजीगत माल पर विचार नहीं किया जाता यदि उक्त पूँजीगत माल का मूल्य पूर्णतया परिशोधित है। तथापि जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है, आयातित पूँजीगत माल का मूल्य 8 वर्ष की अवधि में विभाजित किया जाएगा। यदि शुल्क मुक्त रूप से आयातित किसी पूँजीगत माल को लीजिंग कम्पनी से पट्टे पर लिया जाता है या ऋण के रूप में लिया जाता है, तो पूँजीगत माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य आयातित निवेश के अधीन शामिल किया जाएगा। तथापि, ऐसे पूँजीगत माल की वापसी पर, इसके मूल्य के अपरिशोधित भाग को परिकलन फार्मूले से निकाल दिया जाएगा।

2. कच्चे माल, उपभोज्यों और अतिरिक्त पुर्जों इत्यादि का आयात :-

वर्ष के दौरान जिस भी कच्चे माल, उपभोज्यों और अतिरिक्त पुर्जों का आयात किया जाता है उन्हें गिना जाता है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि पिछले वर्ष के अन्त में जितना भी कच्चे माल शेष है उसे जोड़ा जाता है और चालू वर्ष के अन्त में बचे कच्चे माल को घटा दिया जाता है जोकि वर्ष के दौरान उपभोग किए गए कच्चे माल का मूल्य होगा। अन्तर - यूनिट हस्तांतरण के रूप में खरीदे गए कच्चे माल को भी शामिल किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा की अन्य निकासी :-

मूल्य संवर्धन का परिकलन करते समय उस विशेष वर्ष के दौरान रॉयल्टी, लाभांश और निर्यात पर कमीशन, विदेशी वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज आदि पर सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा की निकासी को गिना जाएगा। तथापि, जानकारी फीस के कारण निकासी को यथालागू पाँच वर्ष/आठ वर्षों की अवधि में आबंटित किया जाएगा।

4. निर्यात का मूल्य :-

निर्यात के मूल्य का परिकलन करते समय वर्ष के दौरान की गई छी टी ए बिक्री को नहीं गिना जाएगा। तथापि, एन एफ ई पी/एन एफ ई के परिकलन हेतु नीति के पेरा 9.10 और 9 के 10 के अनुसार की गई आपूर्तियों को ध्यान में रखा जाएगा।

एक एकक का विवरण नीचे दिया गया है ताकि वर्ष 1999-2000 हेतु एन एफ ई पी की गणना इस धारणा पर की जाए कि पिछले वर्ष और 1999-2000 के अन्त में कोई आयातित कच्चा माल शेष नहीं था। इस मामले में, वर्ष 1999-2000 के लिए एन एफ ई पी का निम्नानुसार परिकलन किया जाता है :-

1.	पूँजीगत माल का परिशोधित मूल्य (वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान किए गए पूँजीगत माल के आयात का 20%)	(अर्थात् 50.00 लाख रु0 का 20%) 10.00 लाख रु0
2.	कच्चे माल आदि का आयात	100.93 लाख रु0
3.	विदेशी मुद्रा का अन्य बहिर्गमन	10.72 लाख रु0
4.	निर्यात का मूल्य	173.13 लाख रु0

$$173.13 - (10 + 100.93 + 10.72) \times 100$$

एन एफ ई पी = $\frac{173.13}{173.13} = 29.73\%$

टिप्पणी : नोशनल/वास्तविक आधार पर एन एफ ई पी/एन एफ ई का परिकलन : एन एफ ई पी/एन एफ ई की गणना करते हुए, पूँजीगत माल का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य या निशुल्क प्राप्त किए गए कच्चे माल को गिना जाएगा।

परिशिष्ट - 16 ज

एस ई जैड में यूनिटों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पेराग्राफ 9क.5 के अनुसार एस ई जैड यूनिट द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट

(सभी आंकड़े अमेरिकी डालरों में दिए जाएं)

1. यूनिट का नाम
2. रिपोर्ट करने की अवधि
3. विनिर्माण /व्यापार/सेवा की मद
4. उत्पादन/प्रचालन आरम्भ होने की तारीख

क्रमांक	लेन - देन	अमेरिकी डालरों में मूल्य
1.	<p>परिवर्तन/एस.ई. जैड स्कीम में तिमाही के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार अथ शेष</p> <p>1) पूँजीगत माल व कायालय सामग्री</p> <p>2) कच्चा माल, कम्पोनेन्ट, कन्ज्यूमेबल, स्पेआर पार्ट</p> <p>3) संघटक फिनिस्ड मैन्यूफैक्चर्ड प्रोडेक्ट</p> <p>(मद की श्रेणी व मूल्य दर्शाया जाना चाहिए। आयातित पूँजीगत माल के मामले में, इ पी जैड के अन्तर्गत परिशोधन के पश्चात् जो अनुमेय हों उसका बचे हुए मूल्य को दर्शाया जाना चाहिए।)</p>	
2.	पूँजीगत माल व कार्यालय उपकरण जो कि पिछली तिमाही में किसी अन्य ई.पी.जैड/एस ई जैड/ई ओ यू/ई एच टी पी से आयात/क्रय किया गया है, का सी.आई.एफ. मूल्य	
3.	तिमाही में आयातित कच्चा माल/कम्पोनेन्ट, कन्ज्यूमेबल का सी.आई.एफ. मूल्य	
4.	तिमाही के दौरान कमीशन/डिविडेंड/रायल्टी इत्यादि के रूप में खर्च की गयी विदेशी मुद्रा।	
5.	तिमाही के दौरान अन्य एस ई जैड/ई पी जैड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में स्थानान्तरण से प्राप्त किया गया वस्तु का मूल्य	
6.	तिमाही के अंत तक आयात का एफ.ओ.बी. मूल्य।	
7.	अग्रिम लाइसेंसों और स्पेशल ड्यूटी प्री इन्टाइटिलमैट के अन्तर्गत तिमाही के दौरान डी टी ए में की गई आपूर्ति माल/सेवा का मूल्य।	
8.	तिमाही के दौरान अन्तः स्थानान्तरण के अधीन अन्य एस ई जैड/ई पी जैड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों को स्थानान्तरित वस्तु का मूल्य	
9.	पिछली तिमाही के अंत में स्टाक में बचे आयातित कच्चे माल, कम्पोनेन्ट व कन्ज्यूमेबल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य।	
10.	प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 9-क.4 में उल्लेखित फार्मूला के अनुसार शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन जिसमें पिछली तिमाही (क्रम संख्या 8) के अंत तक स्टाक में पड़े हुए आयातित कच्चे माल, संघटक, उपभोज्य के सी.आई.एफ. मूल्य शामिल नहीं हैं।	

अन्य व्यौरा
(मूल्य रूपयों में)

11.	पिछली तिमाही के अंत तक डी टी ए में प्रभावी माल की बिक्री यदि कोई हो,	
12.	पिछली तिमाही तक डी टी ए में अस्वीकृत बिक्री यदि कोई हो	
13.	पिछली तिमाही तक अवशिष्ट/छीजन/अवशेष की बिक्री यदि कोई हो	
14.	एस ई जैड के विकास आयुक्त को सूचित देकर जी आर प्रपत्र के बिना माल का नियात जैसे कि (1) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं अथवा सहयोगियों द्वारा प्रतिस्थापन के उद्देश्य हेतु त्रुटिपूर्ण आयातित माल, ऋण आधार पर आयातित माल, मुफ्त नमूनों का निर्यात, बिना किसी मूल्य के विदेशी सप्लायर या कौलब्रेटर से सर्पलैस माल का उत्पादन परिचालन के लिए आयात, प्रदर्शनी आदि में भाग लेने के लिए आयातित परेषण इत्यादि।	
15.	पिछली तिमाही के अंत तक प्राप्त किए गए स्वदेशी पूँजीगत माल संघटक, उपभोज्य का मूल्य।	
16.	पिछली तिमाही के अंत तक प्राप्त किए गए स्वदेशी माल कम्पोनेन्ट, उपभोज्यों का मूल्य।	
17.	पिछली तिमाही के अंत तक 1 वर्ष से अधिक के लिए बकाया लंबित पढ़े विदेशी मुद्रा के वसूली संबंधी मामले निर्यात की तारीख आयातक का नाम पता धनराशि	
18.	पिछली तिमाही के अंत तक लंबित विदेशी वाणिज्यिक उधार। क) तीन वर्ष से कम अमेरिकी डालर में धनराशि ख) तीन वर्ष से अधिक अमेरिकी डालर में धनराशि	
19.	पिछली तिमाही के अंत तक यूनिट द्वारा विदेशों में किया गया निवेश ¹ क) एक वर्ष से कम अमेरिकी डालर में धनराशि ख) एक वर्ष से अधिक अमेरिकी डालर में धनराशि	

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

- (क) सैम्पल के तौर में आयातित या पुनः निर्माण के लिए परिष्कृत माल को कालम 1(2) में शामिल किया जाना चाहिए।
- (ख) अथशेष में लोन के आधार पर अयात की गई मद का मूल्य या डी ट ए से बिना सी टी-३ के छूट वाली मद की खरीद को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट—16 ठ

नई दिल्ली, दिनांक: ७ अगस्त, 2001

अधिसूचना

सं0. 14/1/2001- ईपीजैड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं0 14/1/2001 दिनांक 19.6.2001 के अधिक्रमण में भारत सरकार एतदद्वारा ईओयू/ईपीजैड और एसईजैड योजनाओं के लिए निम्नानुसार संयुक्त अनुमोदन बोर्ड का गठन करती है:-

1.	अपर सचिव, वाणिज्य विभाग	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
4.	सदस्य (सीमाशुल्क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड	सदस्य
5.	विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
7	संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
8	एक प्रतिनिधि लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से	सदस्य
9.	संबंधित ईपीजैड/एसईजैड के विकास आयुक्त	सदस्य
10.	एक प्रतिनिधि आर्थिक कार्य विभाग से	सदस्य
11.	एक प्रतिनिधि शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय से	सदस्य
12.	एक प्रतिनिधि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से	सदस्य
13.	उप सचिव/निदेशक(ईओयू/ईपीजैड) वाणिज्य विभाग	सदस्य-सचिव

बोर्ड के अधिकार एवं कार्य

1. बोर्ड ईओयू/ईपीजैड/एसईजैड योजना के अंतर्गत ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगा जो समय-समय पर यथाअधिसूचित रूप से अनुमोदन प्रक्रिया के दायरे में नहीं आते हैं।
 2. उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अंतर्गत आवश्यक अधिकारिता के अधीन रहते हुए बोर्ड, जहां लागू हो, वहां औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के आवेदनों पर भी विचार करेगा जहां इस प्रकार का लाइसेंस अनिवार्य है। ऐसे मामलों में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् कार्यवृत्त जारी किए जाएंगे। अनुमोदित कार्यवृत्त के आधार पर विकास आयुक्त आशय-पत्र जारी करेंगे और इसमें निहित शर्तों को पूरा करने पर इसे औद्योगिक लाइसेंस में बदल देंगे।
 3. सभी मामले विकासायुक्त द्वारा अपनी टिप्पणियों सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि एककों को केवल विकासायुक्त रूप से ही सम्पर्क करना पड़े।
 4. एनआरआई और ओसीबी द्वारा किए जाने वाले निवेश समेत विदेशी इक्विटी वाले ईओयू के उन मामलों पर कार्यवाई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा की जाती रहेगी, जो रूप से अनुमोदन प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे मामलों में एफआईपीबी के अनुमोदन के लिए इकाइयां औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) को सीधे ही आवेदन भेजेंगी जिसकी एक प्रति संबंधित विकास आयुक्त को भेजी जाएगी।
- जो मामले रूप से अनुमोदन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, वे रूप से अनुमोदन प्रणाली के तहत उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाएंगे।
5. सार्वजनिक/निजी/संयुक्त अथवा राज्य क्षेत्र में एसईजैड/ईपीजैड की स्थापना करने के लिए सभी आवेदनों पर विचार करना और इस संबंध में समुचित सिफारिशें करना।
 6. एसईजैड तथा उसके किसी घटक के विकास, उसका रख-रखाव तथा प्रचालन करने हेतु अपेक्षित वरस्तुओं एवं सेवाओं का अनुमोदन प्रदान करना।
 7. ईपीजैड/एसईजैड के विकास से संबंधित कोई अन्य मामला।

टिप्पणी: सार्वजनिक/निजी/संयुक्त अथवा राज्य क्षेत्र में एसईजैड/ईपीजैड की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अलग से बैठक की जाएगी।

6. बोर्ड अनुमोदन प्रदान करते रामपाल कोई भी ऐसी सर्त निर्धारित कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।
9. बोर्ड अपने विवेक से अनुमोदन प्रदान कर सकता है अथवा उसकी मनाही कर सकता है।
10. अध्यक्ष को इस बात के लिए प्राधिकृत किया जाता है कि यदि वह किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसा करना जरूरी समझे तो वह बोर्ड में पहले शामिल न किए गए किसी अन्य विभाग अथवा एजेंसी के किसी प्रतिनिधि को सहयोगित कर सकते हैं।

(डी.के. मित्तल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(सं0 14/1/2001-ईओयू)

परिशिष्ट- 43

घरेलू टैरिफ क्षेत्र से निर्यात संसाधन क्षेत्र इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैकनालॉजी पार्क और साफ्टवेयर टैकनालानी पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों और निर्यातोन्मुख यूनिटों को की गई आपूर्तियों पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया

टिप्पणी:- कृपया इस प्रक्रिया पुस्तक का पैराग्राफ 9.29 और 9क.17 देखें।

इसमें नीचे दी गई प्रक्रिया केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु लागू होगी:

2. निर्यात अभियुक्त ईकाईयों और निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई पी जैड) इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क, साफ्टवेयर तकनालाजी पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों में निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्ति किए जाने के लिए डी टी ए से उनके द्वारा की गई खरीदों पर उनके द्वारा अदा किए जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए एग्जिम नीति के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर पात्र होंगे:-

क. ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस ई जैड को डी टी ए से सप्लाई उनके द्वारा निर्यात के लिए माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्ति की जाए और उसमें कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य, पैकिंग सामग्री, पूँजीगत माल, अतिरिक्त पुर्जे, उपकरण रखने के लिए सामग्री इत्यादि, जिन पर ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस ई जैड यूनिटों द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर वास्तव में अदा किया गया है, शामिल होंगे।

ख. केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र पर विचार करते हुए ई एच टी पी/एस टी पी नामित अधिकारी अथवा विकास आयुक्त अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखेंगे कि की गई खरीद यूनिटों द्वारा निर्यात के लिए माल के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं और/या निर्यात उत्पाद के लिए प्रयुक्ति की जाएगी।

3. इस सम्बन्ध में अनुपालन किए जाने वाली प्रक्रिया इसके बाद निर्दिष्ट की गई है और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा:

प्रक्रिया:

(1) केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति हेतु यूनिट निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में संबंधित ई पी जैड/एस ई जैड के विकास आयुक्त अथवा ई एच टी पी/एस टी पी के नामित अधिकारी को दावा प्रस्तुत करेगा।

(2) ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस ई जैड यूनिटों के परिसर में जैसे ही माल पहुंचता है, इसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखे गए माल प्राप्ति रजिस्टर में की जाएगी। रजिस्टर में माल का विवरण, मात्रा, क्रय का स्रोत और सी फार्म जिसके प्रति क्रय किया गया है, दर्शाया जाएगा जिसका जोन/सीमाशुल्क प्रशासन के प्राधिकृत स्टाफ द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। अनुलग्नक-2 के अनुसार दावे से संबंधित माल प्राप्ति रजिस्टर के सत्यापन से संबंधित सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र, अपने दावे के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय ब्रिक्री कर की प्रतिपूर्ति केवल उन यूनिटों के लिए अनुमेय होगी जो (पंजीकरण और ब्रिक्री) नियम, 1957 के साथ पठित केन्द्रीय ब्रिक्री अधिनियम, 1956 की धारा 7 के सम्बन्ध में ब्रिक्री कर प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत हैं और इसे संबद्ध फाइल में रखने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र कार्यालय के ब्रिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ई पी जैड/ई ओ यू/एफ टी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट के लिए अलग से केन्द्रीय ब्रिक्री कर पंजीकरण प्राप्त किया जाएगा।

(4) दावे केवल तभी रवीकार्य होंगे जब ई ओ यू/ई पी जैड/एस ई जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट के बैंक खाते अथवा उनके खाते से जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किए गए हों।

(5) निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

(क) सनदी लेखापाल से सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र, जो निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार हो, बांडेड परिसरों में अनुलग्नक-2 में उल्लिखित माल की प्राप्ति को प्रमाणित करता हो, आपूर्तिकर्ता के मूल बीजक/बिल की जांच और प्रत्येक बीजक/बिल के प्रति भुगतान का प्रमाण तथा सी फार्म के साथ मिलान:-

सनदी लेखापाल फर्मों के पात्रता मानदण्ड

(1) जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी राज्यों, अंडमान और निकोबार दीपों और लक्षद्वीप राज्यों में स्थित यूनिटों के मामले में सनदी लेखापाल फर्म कम से कम अकेले स्वामित्व वाली फर्म होनी चाहिए जो एफ सी ए हो और फर्म के पास पूर्ण कालिक कार्यरत हो।

(2) ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में स्थित साझेदार सनदी लेखापाल फर्मों के मामले में वे दो पूर्ण कालिक साझेदार हों, जिनमें से एक एफ सी ए हो।

(3) अन्य क्षेत्रों में स्थित यूनिटों के मामले में साझेदार सनदी लेखापाल फर्मों में कम से कम एक पूर्ण कालिक साझेदार हो,

(4) ऊपर (1) में उल्लिखित क्षेत्रों हेतु सनदी लेखापाल फर्म उस क्षेत्र में स्थित हो जहाँ यूनिट स्थित है अन्यथा की (3) अर्हता लागू होगी ।

(ख) सप्लाई करने वाली यूनिट को क्रेता द्वारा जारी किए गए सी फार्म की फोटोस्टेट प्रति, जोकि यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिपत्रक के संदर्भ सहित क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्षांकित की गई हो । सी फार्म क्षेत्र प्रशासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपर्युक्त पृष्ठांकन जैसे "निरस्त/केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति की गई" करने के बाद यूनिट को लौटादिया जाएगा और फोटोस्टेट प्रति संबंधित फाइल में रखने के लिए अधिकारी के पास रहेगी । केवल पृष्ठांकन करते समय जिन मद्दों हेतु केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति की गई है उन्हें निरस्त बताया जाए और फोटोप्रति अधिकारी द्वारा संबंधित फाइल में रखी जाएगी । सी फार्म दुबारा प्रयोग करने की स्थिति में स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियों से जाचं के समय पड़ताल की जाएगी । फर्म उस फाइल की संख्या बताएगी जिस पर मूल दस्तावेज दिए गए हों । संबंधित फाइल में रखी जाएगी । यदि मूल रसीद उपलब्ध न हो और भुगतान बैंक के जरिए किया गया हो तो बैंक विवरणी जिसमें चैकों का ब्यौरे से मेल खाता हो, जैसा कि अनुलग्नक-2 और उसकी तालिका में विनिर्दिष्ट किया गया है, उसे बीजक के प्रति चैक/ड्रॉफ्ट द्वारा किए भुगतान के सबूत के तौर पर प्रस्तुत करें ।

(6) प्रतिपूर्ति केवल सी फार्म के बदले केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान तक सीमित होगी ।

(7) ई ओ यू/ई पी जैड/ई एफ टी पी/एस टी पी/एस ई जैड उन व्यक्तियों का नाम भी बताएगी जो सी फार्म पर हस्ताक्षर करने के लिए फर्म द्वारा प्राधिकृत है और उसके/उनके नमूना हस्ताक्षरों की तीन प्रतियाँ प्रस्तुत करेगी जोकि यूनिट की संबंधित फाइल में रखी जाएगी ।

(8) क्षतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर की जाएगी । तीन महीने के पूरा होने के 6 महीने की अवधि जिसमें दावा उठाया गया है, के भीतर दावित नहीं किया गया, तो सामान्यतः क्षतिपूर्ति प्रतिवार नहीं किया जाएगा । किश्तों में भुगतान के प्रति माल की वसूली के मामले में केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति का दावा उस तिमाही में किया जाएगा जिसमें बीजक बिल के प्रति पूरा भुगतान किया गया हो । विशेष मामलों में, विकास आयुक्त इस बात की सन्तुष्टि करने के बाद कि विलम्ब किसी सही कारण से या आवेदन-पत्र पर विचार कर सकता है ।

(9) केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति हेतु एक तिमाही के लिए केवल एक समेकित दावा प्रस्तुत किया जाएगा । किसी पूरक दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(10) किसी एक बीजक पर 100 रुपये से कम राशि के लिए केन्द्रीय बिक्री कर हेतु प्रतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(11) केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु विकास आयुक्त/ई एच टी पी/एस टी पी का नामित अधिकारी वितरण प्राधिकारी होगा जो यूनिटों को भुगतान करेगा। सभी दावे बाद में किए जाने वाले आडिट के अधीन होंगे।

(12) यूनिट सभी मूल दस्तावेजों यानी मूल बीजक/बिल, धन रसीद, बैंक विवरणिका की रेंडम/सेंपल चेकिंग हेतु तीन वर्षों हेतु सुरक्षित रखेगी और विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा मंगवाए जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगी। तिमाही विशेष के दावों के 5 प्रतिशत की रेंडम चेकिंग सीरियल नम्बरों के आधार पर कम्यूटर द्वारा बनाई विवरणिकाओं के माध्यम से अलग तिमाही में किए जाएंगे। रेंडम लिस्ट विकास आयुक्त द्वारा व्यक्तिक तौर पर तैयार की जाएगी।

(13) केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के दावे में किसी यूनिट के द्वारा भारी मूल अथवा अनियमितता का पता लगने पर उस यूनिट के विरुद्ध एफ टी डी आर अधिनियम के तहत भुगतान की राशि को वसूल करने और जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।

(14) सरकार की लेनदारियों यानी लीज रेट, कोर्ट निर्णय के परिणाम राशि अथवा आयकर वसूली नोट आदि दावा राशि अथवा बाद में किए जाने वाले भुगतान से काट लिया जाएगा।

परिशिष्ट - 16 च

निर्यातोन्मुख यूनिटों के लिए क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट शर्तें

1. चावल

- (1) चावल (बासमती और गैर बासमती) का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य, जब भी लागू होगा, के अधीन होगा।
- (2) निर्यात पैकेज के लेबल पर चावल की किसम और उद्गम देश का नाम लेखा जाएगा। चावल का निर्यात एपड़ा के साथ उपर्युक्त रूप से पंजीकृत ब्रांड नामों के अधीन होगा जो नामों की लैबलिंग और पंजीकरण से संबंधित मामलों में नोडल एजेंसी होगी।
- (3) यूनिट की क्षमता के संबंध में अनुमोदन खात्य प्रसंसकरण और उद्योग मंत्रालय के परामर्श से दिया जाएगा।
- (4) ई.ओ.यू./ई.पी.जेड चावल मिलों को उनके द्वारा निर्यातित मात्रा की सीमा तक लेवी आदेशों की छूट होगी।

2. सूती धागा

40 काउंट और इससे कम रेज में सूती धागे के विनिर्माण हेतु अनुमोदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18/1/99 को जारी 1999 के प्रेस नोट संख्या-2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

3. चाय

निर्यातीन्मुख ईकाई स्थापित करने के लिए अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा ।

- (1) चाय की डी.टी.ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (2) भारतीय “चाय लोगों” के प्रयोग की अनुमति चाय बोर्ड की अनुमति से दी जाएगी ।
- (3) इंस्टेड चाय की डी.टी.ए बिक्री, चाय बैंग या बल्क के रूप में निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 20% तक अनुमत होगी ।
- (4) नीति के पेरा 9.20 के अनुसार चाय यूनिटों को चाय अपशिष्ट की बिक्री की अनुमति दी जाएगी ।

4. काफी

आयातित काफी का निर्यात संबंधित अधिनियम के तहत काफी बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होगा ।

5. मॉस प्रसंस्करण

यूनिटों की स्थापना के लिए अनुमोदन संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन द्वारा स्थापना स्थल संबंधी पूर्व अनुमति के अधीन होगी ।

6. पेट्रोलियम उत्पाद

ई ओ यू योजना के अधीन पेट्रोलियम तेल शोधक कारखानों की स्थपना के लिए प्रस्तावों के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की पूर्व अनुमति जरूरी होगी ।

7. ग्रेनाइट

- (1) ग्रेनाइट ई ओ यू यूनिटों को न्यूनतम अपेक्षित क्षमता निम्नलिखित होगी :
 - (क) स्लैब्स (केवल 40 हजार वर्ग मीटर न्यूनतम क्षमता दो गेंग आरों सहित)
 - (ख) टाइल्स (केवल 50 हजार वर्ग मीटर न्यूनतम क्षमता दो ब्लाक कटर सहित)
 - (ग) मोनूमेंट्स (केवल 20 हजार वर्ग मीटर न्यूनतम क्षमता एक सर्कुलर आरों * सहित)
 - (घ) स्लैब्स, मोनूमेंट्स और टाइल्स (50 हजार वर्ग मीटर)
- (2) सामान्यतः मिश्रित कच्चे माल पर जोर नहीं दिया जाएगा किन्तु ग्रेनाइट उत्पादों के मामले में ऐसा जरूरी हो सकता है जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता सरकारी पट्टे आदि के लिए जरूरी है ।

8. पुष्पोत्पादन/बागवानी निर्यातोंमुख यूनिटें

निर्यातोंमुख एकक अन्य ठेके पर काम करने वाले किसानों के खेतों में इस्तेमाल के लिए निम्नलिखित सिंचाई संबंधी उपकरणों का आयात कर सकते हैं क्योंकि ये अधिसूचना संख्या 126-सी यू एस/94 दिनांक 3 जून, 1994 के परिशिष्ट - 1 में सूचीबद्ध ग्रीन हाउस उपकरणों में शामिल हैं।

<u>क्रमांक</u>	<u>उपकरण का नाम</u>	<u>एच एस डी सं0</u>
1.	फिल्टर्स	84.21
2.	ड्रिफ्लाइंस और ड्रिप फिटिंग्स	84.24
3.	माइक्रो स्प्रिंकलर्स और मिस्टर्स	84.24
4.	एग्रीकल्चर स्प्रिंलर्स	84.24
5.	फर्टीलाइजर टैंक्स्	84.24
6.	वाल्स	84.81
7.	फर्टीलाइजर पम्पस और कैमिकल इंजेक्शंस	84.13

तथापि, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन, पुष्पोदन/बागवानी ई ओ यू के विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर सामान्य निर्यात उत्पादन के अलावा उपर्युक्त उपकरणों की मदद के साथ अन्य स्थान पर भी किया जा सकता है।

9. उच्च ग्रेड का लौह अयस्क

गोवा मूल और रेडी मूल के लौह अयस्क जिसका इस समय एम.एम.टी.सी के माध्यम से सरणीकृत किया जाता है को छोड़कर उच्च ग्रेड अर्थात् 64% लौह अयस्क और अधिक के निर्यात का प्रस्ताव, अनुमोदन बोर्ड द्वारा वार्षिक मात्रा आबंटन के अधीन है।

टिप्पणी : औषधियों, दुग्ध उत्पादों आदि जैसे किसी केन्द्रीय/राज्य कानून के तहत यूनिटें अलग से लाइसेंस प्राप्त करेंगे।

परिशिष्ट - 26 क

सेवा प्रदायकों के लिए सनदी लेखापाल/लागत और निर्माण लेखापाल के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्ज..... के अवधि के लिए निर्धारित रजिस्टर और संबंधित रिकार्डों की भी जाँच कर ली है और एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि :

मैसर्ज.....(आवेदक का नाम और पता) ने निर्धारित लाइसेंसिंग वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से निम्नलिखित विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा के लिए प्रदत्त सेवाओं के लिए मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा उनकी जाँच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में, हमने बैंकर/विदेशी मुद्रा अर्जन के सनदी लेखाकार से विवरणियों की जाँच और सत्यापन कर लिया है। अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के संदर्भ में ऐसा खर्च जैसे ट्रैवल एजेंट/टॉर ऑपरेटर, क्रयू और केटरिंग रसाफ के रहने और खानपान के लिए विदेशी एयरलाईन्स, संयुक्त राष्ट्र संगठनों और राजनयिक मिशनों और प्राधिकृत डीलरों से किसी प्रमाण पत्र तथा अन्य विषयों जोकि विदेश व्यापार महानिदेशालय के नीति ज्ञापन संख्या 60/97-2002 दिनांक 24.12.98 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, के खर्चों का विवरण सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

1. उपर्युक्त विवरणी में दी गई वित्तीय सूचना संगत रजिस्टर एवं रिकार्डों के समरूप है और सेवा प्रदायक द्वारा बनाई गई लेखा पुस्तिकाओं में सम्मिलित हैं तथ सत्य और सही है।
2. यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई सूचना सभी प्रकार से सत्य और ठीक हो, इसका कोई भाग असत्य या भ्रामक नहीं है और कोई प्रासंगिक सूचना न तो छिपायी गई है और न ही गलत दी गई है।
3. न तो मैं, न ही मेरा कोई साझीदार/निदेशक ही उक्त प्रतिष्ठान या उससे संबद्ध प्रतिष्ठानों का कोई भागीदार/निदेशक या कर्मचारी है।
4. मैं/हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाण पत्र में दिया गया कोई भी विवरण यदि गलत या झूठा सिद्ध होता है तो मैं/हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जोकि कानून में या अन्यथा निर्धारित हों, के लिए उत्तरदायी होऊँगा/होंगे।

(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर/सील)
(सनदी लेखाकार/लागत और निर्माण लेखाकार)

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

पूरा पता :

सदस्यता संख्या :

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 31st August, 2001

No. 34(RE-2001)/1997—2002

No. 01/94/180/051/AMO2/PC IV.—In exercise of powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997—2002, as notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-1997, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook (Vol. 1). (RE-01), 1997—2002.

- 1) Paragraph 7.28 A (ii) is amended to read as :

“If the export obligation is fulfilled in terms of quantity but there is shortfall in terms of value, no penalty will be imposed if the minimum prescribed value addition (or positive value addition, as the case may be) for the particular licence has been achieved. (In case the actual value addition imposed is lower than the minimum prescribed value addition, no penalty will be imposed if the former has been achieved).

However, in case the exporter fails to achieve the required minimum prescribed value addition (or positive value addition, as the case may be), he shall be required to deposit an equivalent amount through TR in the authorised branch of Central Bank of India indicating the “Head of Account :0037 - Customs and Minor Head: 101- Imports” so that the deposited amount and the FOB value realised in Indian Rupees together account for the minimum prescribed value addition (or positive value addition, as the case may be) over the CIF value.”

- 2) The second paragraph 7.28 B (ii) is amended to read as :

“However, in case he fails to achieve minimum prescribed value addition, he shall be required to deposit an equivalent amount through TR in the authorised branch of Central Bank of India indicating the “Head of Account :0037 - Customs and Minor Head: 101- Imports so that the deposited amount and the FOB value realised in Indian Rupees account for the minimum prescribed value addition over the CIF value.”

- 3) The first sentence of paragraph 7.29 is amended as under:

“The customs duty with interest to be recovered from the licensee on account of regularisation or enforcement of BG/ LUT, as the case may be , shall be deposited by the licence holder in relevant Head of Customs Revenue i.e. Major Head : 0037- Customs and Minor Head: 101 – Import Duties in prescribed T.R. Challan within 30 days of the demand raised by the licencing/ customs authority and documentary evidence shall be produced to this effect to the licencing/ customs authority immediately.”

- 4) Para 9.7 pertaining to the "Import of Capital Goods" is substituted by the following:

"In the case of EOU/EPZ/EHTP/STP units, import of capital goods including second hand capital goods, may be undertaken as per LUT."

- 5) Para 9.29 A(c), is substituted by the following:-

"FOB value of export of an EOU/EPZ/EHTP/STP units may be clubbed with FOB value of export of its parent company in the DTA or vice versa for the purpose of according Export House, Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House status."

- 6) Para 9.29 A(d), is substituted by the following:-

"100% FDI in the manufacturing sector is permissible to EOU/EPZ/EHTP/STP units. For FDI in services and trading sector, the sectoral norms as notified by the Department of Industrial Policy and Promotion shall be applicable."

- 7) Para 9.30(b), is substituted by the following:-

"In respect of items not covered by Appendix-41, Development Commissioner shall fix the wastage keeping in view the norms notified under Duty Exemption Scheme. For items not covered by these two, the Development Commissioner, if considered necessary, could send proposals to the Board of Approval for decision.

All cases where wastage norms have not been fixed by the Development Commissioner within 45 days from the date of receipt of application, the same shall be referred to the Board of Approval for information along with reasons for delay."

- 8) The opening para 9.37 b)(vi) is substituted by the following:-

"Change^f of location/expansion: To permit change of location from the place mentioned in the LOP/LOI to another and/or include additional location provided that:"

- 9) Para 9.37 b) (x) is substituted by the following:

"Merger of two or more EOU/EPZ units: To permit merger of two or more units into one unit provided the units fall within the jurisdiction of the same DC."

- 10) Para 9.37 b) (xi) is deleted.

- 11) In paragraph 9-A.4, the last sub-para is substituted by the following:-

"For annual calculation of NFE, the value of imported capital goods and lumpsum payment of foreign technical know-how fee shall be amortized as under."

- 12) Paragraph 9-A.8 is substituted by following:

"SEZ units may sell goods including by products and services in the DTA on payment of applicable duties on the basis of self-certification."

- 13) In paragraph 9-A.11 (iv) the last sentence shall be read as under:

"Sectoral norms as notified by the Government shall apply to foreign investment in services and trading activities."

- 14) In paragraph 9-A.12, the following new sub-para (d) is incorporated:-

"(d) SEZ units may be permitted to remove moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers and patterns and drawings to the premises of sub-contractors subject to the conditions that these shall be brought back to the bonded premises of SEZ units on completion of the job work within a stipulated period"

- 15) Paragraph 9-A.19 (iii)(b) is deleted.

- 16) In paragraph 9-A.19 (iii), the following two new sub-para (g) and (h) are added:

"(g) Approve applications for setting up of units in SEZ other than proposals for setting up of unit in the service sector (except software and IT enabled services, trading or any other service activity as may be delegated by the BOA), provided that the item of manufacture does not require an industrial licence under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951.

(h) Green Card will be issued by the DC concerned to SEZ units automatically after execution of Legal Undertaking."

- 17) Paragraph 10.3 is amended as under:

"In respect of supply of goods to EOU/ EPZ/SEZ/ EHTP / STP in terms of paragraphs 10.2(b) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraph 10.3 (a), (b) and (c) of the Policy.

- 18) A last sub para is added to Paragraph 10.7 as under:

"Supplies under paragraph 10.2 (b) of the Policy would be eligible for refund of Terminal Excise Duty (TED) to the EOUEPZ units upon furnishing proof of payment of TED and a disclaimer certificate from the DTA supplier that he shall not be claiming refund of TED paid by him."

- 19) The Annexure to Appendix 16 BBB is substituted by the relevant enclosure to this Public Notice.

- 20) The Appendix 16 E and the Annexure 1 thereto are hereby substituted by the relevant Appendix and Annexure appended to this Public Notice.
- 21) Appendix 16 F and H are substituted by the relevant enclosure to this Public Notice.
- 22) Appendices 16 J and 16 K are deleted.
- 23) Appendix 16 L is added as per the relevant enclosure to this Public Notice.
- 24) Appendix 26 A is added as per annexure to this Public Notice.
- 25) The following amendments/ corrections are made in Appendix 28 A as under:
- (a) Product Group: Engineering (Product Code: 61)
 - The following entry is corrected as under:

S.No	Description of Export Product	DEPB Rate	Value Cap
229	Steel pegs	13.00	Rs. 40/ kg

- (ii) The following entries are amended as under:

S.No	Description of Export Product	DEPB Rate	Value Cap
93	2" Galvanised/ Zinc Coated Bungs	14.00	Rs 95/ kg
94	2" Galvanised/ Zinc Coated Flange	14.00	Rs 90/ kg
96	3/ 4" Galvanised Bungs with Rubber Gaskets	14.00	Rs 96/ kg
98	3/ 4" Galvanised / Zinc coated Bungs	14.00	Rs 140/ kg
99	3/ 4" Galvanised/ Zinc coated Flange	14.00	Rs 100/ kg
227	Steel Clamp (galvanised and ungalvanised)	15.00	Rs 70/ kg
438	2" Bungs with or without washer/ gasket	14.00	Rs 88/ kg

(b) Product Group: Chemicals (Product Code : 62)

- (i) The following entry is amended as under:

S.No	Description of Export Product	DEPB Rate	Value Cap
777	Potassium Penicillin -G First Crystal/ Penicillin Potassium V First Crystal /BP/ USP/ ISP	16.00	Rs 600/- BOU

(c) Product Group: Electronics (Product Code : 83)

- (ii) The following entry is amended as under:

S.No	Description of Export Product	DEPB Rate	Value Cap
43	Televisions – Colour of all Screen sizes including projection TV and video projector in CKD/ SKD/CBU thereof	22.00	(i) Rs 4200 per piece for size upto and including 17" (ii) Rs 8700 per piece for size above 17" (excluding 17")

- 26) The address and contact numbers of M/s American Quality Assessors (India) Pvt Ltd (Under the Offices of AQA, USA) appearing at S.No 12 of Appendix 32 A and S.No 12 of List A under Appendix 32 B is amended to read as under:

3-6-157, Victory Vihar, 4th Floor,
Himayathnagar, Hyderabad –500 029
Tel: 040-3222894,3222895 Fax: 040-3223023
Email: aqa@aqa-india.com / srihari@hd1.vsnl.net.in

- 27) The following clarification is issued with reference to Appendix 41 that pertains to the “Norms of Scrap/ Waste Material for an Export Product under EOU and units in EPZ”.

The wastage norms for Combed Cotton Yarn at S.No 100 of Appendix 41 of the Handbook as per the table given below would be applicable w.e.f. 01.12.1999 i.e the date of issue of Public Notice No 42 (RE-99).

S.No	Goods Manufactured	Imported Goods used	Percentage of scrap or waste on imported goods
100	a)Combed Cotton Yarn below 40's b)Combed Cotton yarn 41's and above	Cotton	25%
		Cotton	30%

28) Appendix 43 is substituted by the relevant enclosure to this Public Notice.

29) The Following addition is made in Appendix 51 B pertaining to the “List of Agencies Authorised to Issue Certificates of Origin – Non Preferential” under the State Head Delhi

DELHI

8. M/s Laghu Udyog Bharti,
1E/11, Swami Ramtirth Nagar, Jhandewalan Extn,
New Delhi 110055

This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Annexure of Appendix BBB

ANNUAL PERFORMANCE REPORT OF SEZ UNITS

PART - A		
	Rs. in lakhs	US \$'000
1. Name of the unit		
2. LOP No. & Date		
3. Item of Manufacture		
4. Date of commencement of commercial production		
5. Opening balance of Capital Goods :		
6. Import of capital goods during the year		
7. CG received under Inter-Unit Transfer during the year		
8. Outflow of FE on account of know how fees		
Total		
9. Opening balance of imported RM, consumables, spares, etc. at the beginning of the year		
10. RM, Consumables, spares, etc. imported during the year		
11. RM, consumables, spares, transferred to other units under inter unit transfer		
12. RM, consumables, spares received under inter unit transfer		
13. Imported RM, Consumables, spares, etc. consumed during the year		
14. Closing balance of imported RM, consumables, spares, etc at the end of the year		
15. Outflow of FE on account of interest on ECB, Export commission, foreign travel, royalty/dividend payment etc		
Total		
16. FOB value of exports		
17. Supplies made under para 9.10		
Total		
18. TA sales- (I) Finished goods (II) Rejects (III) Waste &		
19. NFE actually achieved		
20. Export Performance actually achieved		

Part B (as on 31.3.2001)		
Authorised capital		
Paid up capital		
Foreign Direct Investment -		
(I)Approved (Since inception)	(II)	
Actual Inflow		
NRI capital		
(I)Approved (Since inception)	(II)	
Actual Inflow		
Indian Equity		
	Supervisory	Non-supervisory
	Total	
Employment :	Male	
	Female	
	Total	

Notes :-

- 1) The above information should be given separately for each Letter of Permission.
- 2) Figures should correspond to financial year April-March.
- 3) The information given in the formats should be authenticated by the authorized signatory of the unit and should be certified for its correctness by a Chartered Accountant with reference to the account records and registers maintained by the unit.

APPENDIX – 16 E

Guidelines for monitoring the performance of EOU/EPZ/SEZ units

(1) The annual review of performance of each operational unit and its compliance with the conditions of approval shall be undertaken by the Development Commissioner before the end of the first quarter of the following financial year;

(2) A summary of annual performance review will be sent by each Development Commissioner to the Ministry of Commerce for information under the three formats indicated below latest by 30th June every year;

Proforma I: Comparative statement of performance and monitoring as compared to previous year;

Proforma II: Summary of annual performance of the EOU/EPZ/SEZ units, sector-wise with sectoral sub-totals.

Proforma III: Unit-wise statement on NFE and NFEP showing the result of review.

(A) EOU / EPZ units:

CRITERIA FOR ANNUAL MONITORING:

The criteria for keeping the unit under watch or initiating penal action in respect of EOU/EPZ units would be as follows :

- i) Watch – If there is shortfall in achieving the NFEP and/or Export Performance (as per norms in Appendix – I) at the end of 1st and IIInd year;
- ii) Penal action -If at the end of 3rd or subsequent year the NFEP / EP are not achieved as per Appendix-I of Exim Policy, Show Cause Notice will be issued. After consideration of reply of unit, if it is noted that the unit has not achieved NFEP/EP as per policy the Development Commissioner would initiate penal action under the FT(D&R) Act, 1992;
- iii) If penal action has been initiated against a unit on account of shortfall in NFEP/EP as stated above in a particular year and it defaults again in subsequent year(s), fresh penal action will be initiated against the unit. If however, during the adjudication proceedings, it comes to light that unit has improved performance and now fulfilling NFEP/EP as per policy, DC concerned would consider that fact before taking a decision.

METHOD OF MONITORING:

- i) In all cases of debonding where the unit has imported inputs and failed to fulfil the conditions of LOP with regard to NFEP/EP, appropriate steps are to be taken for penal action after issuing Show Cause Notice to the units. Steps may also be initiated for cancellation of LOP/LOA of units which is not operating for more than a year;
- ii). The Minimum export obligation expressed as minimum FOB value of exports shall be as per the norm for the 5 year period for various sectors given in Appendix – I of Exim Policy from time to time;
- (iii) NFEP is to be calculated as per Para 9.29 of Exim Policy. For purpose of uniformity, guidelines for calculation of NFEP given in Annexure – I, may be followed.
- iv) Units which have not completed one year, from the date of commencement of commercial production, will not be monitored. In case a unit has completed less than five years from the date of commencement of commercial production it will be monitored for the number of completed years. Annual monitoring in the cases of old units which have completed more than five years will be undertaken for only such number of years which fall in the second block of five years

v) Concurrent joint monitoring of EOU / EPZ units:

- a) The performance of EOU / EPZ units would be jointly reviewed by the Development Commissioners of EPZs and concerned Customs / Central Excise Officers on six monthly basis i.e. April - September each year to be completed in the following quarter on the basis of QPRs furnished by the EOUs and for the full financial year on the basis of APR to be completed in the following quarter. The formats of QPR/APR have been prescribed in the LUT at Appendix B and Appendix BB.
- b) Joint review of EP/NFEP of the EOUs would be conducted by the DC / JDC and jurisdictional Deputy Commissioner / Asstt Commissioner of Customs and Central Excise in the office of Commissioner of Customs / Central Excise where representative of units would also be invited. This will help them to understand the scheme and clear the doubts about operation. The Development Commissioner are advised to identify the number of Customs and Excise Commissioners where the meetings are to be held and work out a schedule for visiting each of these places. It is suggested that at least two places should be visited each month, so that all places are covered within a period of three months. Some places may be covered by JDC and in the next six months, these could be interchanged between JDC and DC. For EPZ/SEZ units, this review will be done in the Zone itself.
- c) For publicising the scheme, advertisement in the local papers may be arranged before the date of such meetings. Promotion program may be organised in collaboration with local industry, Association or any other organisation which has good presence in the area. General Manager of District Industries Center may be associated.
- d) For each existing unit, review should be done at length to understand their problems and their possible resolution. Efforts should be made to identify the reasons for shortfall / poor performance and unit-wise action plan should be prepared for removal of bottlenecks. It should be ensured that the unit should have an export promotion strategy as well as tentative targets for next few years, so that it has an idea as to what is to be achieved by them. Effective action should be taken against erring units to discourage any misuse of the scheme.
- (e) For units under implementation, separate review should be held so that their issues could be resolved.
- (f) At such places, if any infrastructure gaps are noticed, District Administration may be advised to prepare projects which can be routed through State Government to the Ministry for approval under CIB Scheme.
- g) Based on the joint review Development Commissioner concerned would prepare a report for information of the Department of Commerce and CBEC and suggest corrective measures to enable the defaulting units to fulfill their obligation as per Exim Policy / Customs Notifications.

(B) SEZ UNITS:**QUARTERLY AND ANNUAL MONITORING**

- i) The performance of the SEZ units shall be monitored by a Committee as provided for in para 9A-5 of the Exim Policy.
- ii) The performance of the SEZ units to be monitored each quarter period on the basis of reports received in Appendix 16 H.
- iii) Annual monitoring would be undertaken on the basis of APR prescribed in Annexure I of Appendix 16-BBB. However, penal action is to be initiated only if NFE achieved is negative at the end of 3rd or subsequent years. In case of existing EPZ units converting into SEZ scheme, the date of commencement of commercial production under the EPZ scheme will be the date for reckoning the number of years completed by the units for the purpose of monitoring.
- iv) During the joint review, efforts should be made to identify the reasons for shortfall/poor performance and unit-wise action plan should be prepared for removal of bottlenecks through such a review.
- (v) Based on the joint review, Development Commissioner concerned would prepare a report for the information of the Department of Commerce and CBEC and suggest corrective measures to enable the defaulting units to fulfil their obligations as per Exim Policy/Customs Notifications

(c) OTHER CONDITIONS:

Development Commissioner will monitor Foreign Exchange realization/remittance of EOU/EPZ/SEZ units in coordination with the concerned General Manager of RBI as per instructions issued on the subject vide RBI circular No. COEXD. 3109/05.62.05/99-2000 dated 21.2.2000.

ANNEXURE – I**CALCULATION OF NFEP/NFE**

While calculating NFEP/EP achieved, following basic components are to be taken into consideration:

- i. Amortised value of capital goods and technical know how fee
- ii. Value of import of R. M. (which is consumed during the year and consumables, spares, etc.).
- iii. Other outflow of foreign exchange towards royalty, interest on external commercial borrowings etc.
- iv. Value of physical exports effected excluding DTA sales but including supplies made under para 9.10 and 9A.10 of the policy.

1. **Amortised Value of Capital Goods:** For this purpose as much value of CG is taken into account as indicated in para 9.40 for NFEP and 9A.32 for NFE of the Hand Book of procedure (Vol.I). The CG imported prior to the 5 years period is not taken into

consideration for the purposes of NFEP/NFE if the value of said CG is fully amortized. However where investment in plant and machinery is more than Rs. 5.00 crores, the value of imported CG will be apportioned over a period of 8 years. If any capital goods imported duty free is leased from a leasing company or is taken in loan the CIF value of the capital goods shall be included under the imported inputs. However, on return of such CG its unamortized portion of value would be excluded from the calculation formula.

2. Import of raw material, consumables and spares etc: Whatever R. M. Consumables and spares are imported during the year are taken into account. However, it should be noted that whatever R. M. is in balance at the end of the previous year is added while the RM at the end of the current year is deducted which will give the amount of RM consumed during the year. RM purchased as inter – unit transfer is also included.

3. Other outflow of foreign exchange: All the foreign exchange outflow on account of royalty, dividends, commission on exports, interest on external commercial borrowing etc., during the particular year has to be accounted for while calculating value addition. However outflow on account of know-how fee would be apportioned during a period of five years/eight years as applicable

4. Value of exports: While calculating value of exports, DTA sale made during the year are not to be accounted for. However, supplies made in accordance with the para 9.10 and 9A.10 of the Policy will be taken into consideration for calculation of NFEP/NFE.

Given below are details of a unit so as to calculate the NFEP for the year 1999 – 2000, on the presumption that no imported RM was in balance at the end of previous year as well as at the end of 1999-2000. In this case, the NFEP for 1999-2000 is calculated as below: -

1. Amortised value of CG. (20% of import of CG made during the years 1995-96 to 1999-2000)	(i.e., 20% of Rs. 50.00 lakhs) Rs. 10.00 lakhs
2. Impact of R. M. etc	Rs. 100.93 lakhs
3. Other outflow of F. E.	Rs. 10.72 lakhs
4. Value of exports	Rs. 173.13 lakhs

$$\text{The NFEP comes to} = \frac{173.13 - (10 + 100.93 + 10.72) \times 100}{173.13}$$

$$= 29.73\%$$

Note:CALCULATION OF NFEP/NFE ON NOTIONAL/ACTUAL BASIS: While calculating NFEP/NFE, FOB value of the capital goods or raw material received free of cost may be taken into account.

Appendix-16-H**QUARTERLY REPORT TO BE FURNISHED BY UNITS IN SEZ**

Quarterly statement to be furnished by the SEZ unit in terms of paragraph 9A.5 of Handbook of Procedures (Vol I).

(All figures to be given in US\$)

1. Name of the unit :
2. Period of reporting :
3. Item(s) of manufacture/trading/service :
4. Date of commencement of production/operation

S.No.	Transaction	Value in US\$
1.	Opening balance as on the date of conversion/1st day of quarter into SEZ scheme:- i) capital goods and office equipments, ii) raw materials, Components, consumables, spare parts, iii) finished manufactured products (category of items and value to be indicated. In case of imported capital goods, balance value remaining after amortization allowed under EPZ scheme only to be indicated).	
2.	CIF value of CG and office equipments imported / purchased from other EPZ / SEZ / EOU / EHTP during the quarter.	
3.	CIF value of raw materials/ components, consumables imported during the quarter.	
4.	Other foreign exchange outgoes on account of commission/ dividend/ royalty etc. during the quarter.	
5.	Value of goods received from other SEZ/EPZ/EOU/EHTP/STP units under inter-unit transfer during the quarter.	
6.	Fob value of exports till the end of the quarter.	
7.	Value of goods/services supplied in the Domestic Tariff Area against advance licenses and special duty free entitlements during the quarter.	
8.	Value of goods transferred to other SEZ/EPZ/EOU/EHTP/STP units under inter-unit transfer during the quarter.	
9.	CIF value of imported raw materials, components and consumables lying in stock at the close of the quarter.	

10. Net Foreign Exchange Earning as per the formula indicated in paragraph 9-A.4 of the Handbook of Procedure (Vol.I) excluding the CIF value of imported raw materials, components, consumables lying in stock at the end of last quarter (S.No. 9 above)

Other details

(Value in Rupees)

11.	Sale of goods effected in DTA, if any, till last quarter.		
12.	Sale of rejects, in the DTA, if any, till last quarter.		
13.	Sale of waste/scrap/remnants, if any, till last quarter		
14.	Goods exported without GR form under intimation to the Development Commissioner of SEZ such as (i) imported goods found defective for the purpose of replacement by foreign suppliers or collaborators, imported goods on loan basis, export of free samples, surplus goods imported from foreign suppliers or collaborators free of cost for production operations, consignments imported for participation in exhibitions etc.		
15.	Value of indigenous CG procured till end of last quarter.		
16.	Value of indigenous raw materials/ components, consumables procured till the end of the last quarter		
17.	Cases of pending Foreign Exchange realisation outstanding for more than one year at the end of last quarter Date of export : Name of Importer: Address : Amount		
18.	External commercial borrowing pending at the end of last quarter (a) Less than three years Amount in \$ (b) More than three years -do-		
19.	Overseas investment made by the unit at the end of last quarter a) Less than one years Amount in \$ (b) More than one years -do-		

Explanatory Notes:

- a) Finished goods imported as samples or for re-making should be included in column 1 (ii)
- b) Opening balance not to include value of items imported on loan basis or procured from DTA without CT-3 exemption.

APPENDIX- 16-L

New Delhi, dated the August 7 , 2001

NOTIFICATION

No. 14/1/2001-EPZ In supersession of Ministry of Commerce and Industry Notification No. 14/1/2001 dated 19.6.2001, Government of India hereby constitutes combined Board of Approvals for EOU/EPZ and SEZ Schemes as under:-

1.	Additional Secretary Department of Commerce	Chairman,
2.	Joint Secretary Department of Commerce	Member
3.	Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion	Member
4.	Member(Customs) Central Board of Excise and Customs	Member
5.	Director General of Foreign Trade	Member
6.	Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests	Member
7.	Joint Secretary, Ministiy of Science and Technology	Member
8.	A representative from Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	Member
9.	Development Commissioner of the concerned EPZs/SEZs	Member
10.	A representative of Department of Economic Affairs	Member
11.	A representative of Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation	Member

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 12. | A representative of Central Board of Direct Taxes | Member |
| 13. | Deputy Secretary/Director (EOU/EPZ)
Department of Commerce | Member-Secretary |

Powers and functions of the Board:

1. The Board shall consider proposals under EOU/EPZ/SEZ scheme that fall outside the automatic approval procedure as notified from time to time.
2. Subject to necessary empowerment under section 14 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Board, wherever applicable, shall also consider applications for grant of industrial licence wherever such licence is compulsory. Minutes in such cases will be issued after approval of Department of Industrial Policy and Promotion. Based on the approved minutes the Development Commissioner shall issue the Letter of Intent and upon fulfillment of conditions therein convert the same into industrial licence.
3. All Cases would be submitted before the Board by the Development Commissioner along with his comments so that the units have a single interface at the level of Development Commissioner;
4. EOU cases involving foreign equity, including investment by NRIs and OCBs that fall outside the automatic route shall continue to be dealt with by the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). In such cases, the units will apply directly to Secretariat for Industrial Assistance (SIA) for FIPB approval with a copy to the Development Commissioner concerned.

Those falling under the automatic route shall avail themselves of the dispensation available under the automatic route.

5. Consider all application for setting up of SEZ/EPZ in the public/private/joint or State sector and make suitable recommendations in this regard.
6. Approve goods and services required for developing , maintaining and operating SEZ or any component thereof
7. Any other issues concerning development of EPZ/SEZ

Note: Separate meeting will be held to consider the proposal to set up SEZ/EPZ in the public/private/joint or State sector."

General

8. The Board may prescribe any condition, as it may consider necessary while granting approval.
9. The Board may in its discretion grant or refuse the approval.
10. Chairman of the Board may co-opt any representative of any other Department or agency not already included in it, if he finds it necessary for any specific purpose.

Joint Secretary to the Government of India

(D.K.Mittal)

[No. 14/1/2001-EOU]

APPENDIX - 43

Procedure to be followed for reimbursement of Central Sales Tax (CST) on supplies made to Export Oriented Units (EOUs) and units in Export Processing Zones(EPZ), Electronic Hardware Technology Park (EHTP), Software Technology Park (STP) and Special Economic Zones(SEZ)from Domestic Tariff Area (DTA)

Note: Please see paragraph 9.29 and 9A.17 of this Handbook.

The procedure given hereunder shall be applicable for reimbursement of Central Sales Tax.

2. The Export Oriented Units (EOUs) and units in Export Processing Zones (EPZs), Electronic Hardware Technology Park (EHTP), Software Technology Park (STP) and Special Economic Zones (SEZ) will be entitled to full reimbursement of Central Sales Tax (CST) paid by them on purchases made from the Domestic Tariff Area (DTA), for production of goods and services as per Exim Policy on the following terms and conditions:

- (a) The supplies from DTA to EOU/EPZ/EHTP/STP/SEZ units must be utilised by them for production of goods meant for export and/or utilised for export production and may include raw material, components, consumables, packing materials, capital goods, spares, material handling equipment etc. on which CST has been actually paid by the EOU/EPZ/EHTP/STP/SEZ
- (ii) While dealing with the application for reimbursement of CST, the Development Commissioner or the designated officer of EHTP/STP shall see, inter alia, that the purchases are essential for the production of goods meant for export and/or to be utilised for export production by the units

3. The procedure to be followed in this regard is indicated hereinafter and shall be strictly adhered to:

Procedure

- (i) The unit shall present its claim for reimbursement of CST in the prescribed form (Annexure - 1) to the Development Commissioner of the EPZ/SEZ concerned or the designated officer of the EHTP/STP.
- (ii) As soon as the goods are received by the EOU/EPZ/EHTP/STP/SEZ unit in its premises it will be entered in the material receipt register kept for the purpose. The register must show the details of goods, quantity, the source of purchase and the C Form against which purchase is made, etc. which will be subject to periodical check by the authorised staff of the Zone/Customs administration. A Chartered Accountant's

certificate regarding the verification of the materials receipt register relevant to the claim as at Annexure - II shall be submitted alongwith the claim,

(i) The reimbursement of CST shall be admissible only to those units who get themselves registered with the Sales Tax authorities in terms of Section 7 of the CST Act, 1956 read with (Registration and Turnover) Rules, 1957 and furnish a photostat copy of the Registration Certificate issued by the Sales Tax authorities to the Zone office concerned for keeping it in the relevant file.

iv) Claims shall be admissible only if payments are made through the bank accounts maintained by EOU/EPZ/SEZ/EHTP/STP unit or DD emanated from its accounts.

(v) The claim shall be submitted alongwith the following documents:

a) Chartered Accountant's Certificate, from CA, meeting the following criteria, certifying receipt of the goods as shown in Annexure-II in the bonded premises, scrutiny of original invoice/bill of the supplier and proof of payment against each invoice/bill and its reconciliation with 'C' Form:-

Eligibility criteria for C.A. firms:

(i) In case of units located in the States of J&K, Orissa, North-Eastern States, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep, the Chartered Accountant firm should be at least a Sole Proprietorship firm who should be an FCA and engaged full time with the firm.

(ii) In case of partnership Chartered Accountant firms located in the regions indicated in (i) above, should have at least two full time partners, one of whom should be an FCA.

(iii) In case of units located in other regions, the partnership Chartered Accountant firms should have atleast one full time partner, who should be an FCA.

(iv) For the regions indicated in (i) above, the Chartered Accountant firm be located ~~in the~~ area where the unit is situated otherwise qualification of (iii) shall apply.

b) Photostat copy of C Form issued by the EOU/EPZ/EHTP/STP/SEZ to the supplier in the DTA with reference to the counterfoil produced by the unit. The counterfoil of C form will be returned to the unit after making suitable endorsement like 'cancelled/CST reimbursed' duly signed by the authorised officer of the Zone administration. While making the endorsement only, the items for which CST has been reimbursed should be indicated as cancelled. and the photostat copy will be retained by the officer for keeping in respective file. In the event of the same 'C' form being used again, the verification could be done at the time of scrutiny from the self attested photocopies. The firm must indicate the file No. on which the original stands submitted.

- (vi) The reimbursement will be limited to the payment of CST against C Form only.
- (vii) The EOU/EPZ/EHTP/STP/SEZ shall also intimate the name of the person/persons who are authorised by them to sign the C Form and furnish three copies of his/their specimen signature(s) which will be kept in the relevant file of the unit.
- (viii) The reimbursement will be made on quarterly basis. No claim for reimbursement will be normally entertained if not claimed within a period of six months from the completion of the quarter in which the claim has arisen. In case of procurement of goods against payment in instalments, the CST reimbursement claim may be made in the quarter in which the full payment has been effected against the invoice/bill. In exceptional cases, the Development Commissioner may consider delayed applications after satisfying that the delay was due to genuine grounds.
- (ix) Only one consolidated claim for a quarter will be admitted for reimbursement of CST. No supplementary claim shall be entertained.
- (x) The claim for CST reimbursement for the amount below Rs. 100/- on any single invoice shall not be entertained.
- (xi) The disbursing authority for the claim of reimbursement of CST will be Development Commissioner/designated officer of EHTP/STP who will make payment to the units. All claims shall be subjected to post audit.
- (xii) The unit shall preserve for three years all the original documents viz. Original invoice/bill, money receipt/bank statement for random/sample checking and produce the same as and when called for by the office of the Development Commissioner. Random checking of 5% of the claims of a particular quarter should be done in the next quarter through generation of computer statements on the basis of serial numbers. The random list will be generated by the Development Commissioner personally.
- (xiii) In case some glaring error or irregularity is detected against any unit in claiming CST reimbursement, action to recover the amount paid and levy penalty would be taken under FTDR Act against such unit [REDACTED]
- (xiv) Any dues of the Government viz. arrear of Lease rent, amount on account of a Courts decree or Income tax recovery note, etc. will also be deductible from the claim amount or it can be set off from the subsequent payment.

APPENDIX- 16- FSector specific conditions for EOU/EPZ unit:(1) RICE:

- i) Export of rice(both basmati and non-basmati)shall be subject to minimum export price(MEP) whenever inforce;
- ii) The labeling of export package should declare the type of rice and country of origin. The export of rice would be under brand names suitably registered with APEDA which shall be the nodal agency in the matters relating to labeling and registration of brand names;
- iii) The approval shall be granted in consultation with Ministry of Food Processing Industries with regard to capacity of the unit;
- iv) EOU/EPZ rice mills will be exempted from levy orders limited to the quantity exported by them

(2) COTTON YARN:

The approval for manufacture of cotton yarn in the range of 40 counts and below would be subject to conditions mentioned in Press Note No.2 of 1999 dated 18.1.99 issued by the Deptt. of IP&P

(3) TEA:

The approval for setting up EOUs would be subject to the following conditions:-

- i) DTA sale of Tea will not be allowed .
- ii) Use of “India Tea logo” shall be allowed with the permission of Tea Board.
- iii) DTA sale of instant tea would be allowed upto 20% of FOB value of exports in the form of tea bags or bulk.
- (iv) Tea units may be allowed to sell tea waste in accordance with para 9.20 of the Policy.

(4) COFFEE

Export of imported coffee shall be subject to approval from Coffee Board under relevant Act.

(5) MEAT PROCESSING:

Proposals for setting up meat processing units shall be subject to prior clearance of location by the respective State Governments/UT Administration

(6) PETROLEUM PRODUCTS:

Proposals for setting up petroleum refineries under the EOU scheme shall require prior clearance of the Ministry of Petroleum.

(7) GRANITES:

1) Minimum annual capacity requirement for Granite EOUs would be as follows.-

- a) SLABS (if exclusively minimum 40,000 sq.mtrs. with two gang saws)
- b) TILES (if exclusively minimum 50,000 sq.mtrs. with two block cutters)
- c) MONUMENTS (if exclusively minimum 20,000 sq.mtrs. with one circulars saw)
- d) SLABS, MONUMENTS & TILES (50,000 sq.mtrs.)

2) Normally raw material tie-ups are not insisted upon but this may be necessary in cases, such as granite products where availability of raw materials is contingent upon Government leases etc.

(8) FLORICULTURE/HORTICULTURE EOUS:

The EOUs engaged in floriculture/horticulture may import for use at fields of other contract farmers the following irrigation equipment's as these are covered in the green house equipment's listed in Annexure -I notification No.126-Cus /94 dated the 3rd June, 1994 as amended from time to time.

<u>S.NO.</u>	<u>Name of the equipment</u>	<u>HSD No.</u>
1.	Filters	84.21
2.	Driplines & Drip Fittings	84.24
3.	Micro sprinklers & Misters	84.24
4.	Agriculture sprinklers	84.24
5.	Fertilizer Tanks	84.24
6.	Valves	84.81
7.	Fertilizer pumps & Chemical Injections	84.13

It may, however be ensured that not more than 50% production may take place at other identified place with the help of the above equipment besides normal export production on the specified area of floriculture/horticulture EOUs.

(9) HIGH GRADE IRON ORE

Proposals for export of high grade i.e. 64% Fe Iron Ore and above except iron ore of Goa origin and Redi origin are presently canalized through MMTC and its exports would be subject to annual quantity allocation by the BOA.

NOTE: Units will obtain separate licence required under any Central/State law, like drugs, milk products etc.

APPENDIX -26-A

FORMAT OF CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/COST AND WORKS ACCOUNTANT FOR SERVICE PROVIDERS

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed registers and also the relevant records of M/S _____ for the period _____ and hereby certify that:

M/s _____ (full name and address of the applicant) have earned the following foreign exchange from direct and indirect sources in the prescribed licensing year:

The following documents/records have been furnished by the applicant for services provided against Direct/Indirect foreign exchange and have been examined and verified by me/us.

In respect of direct foreign exchange earnings, we have verified the certified statements from the Banker/ Chartered Accountant of Foreign Exchange Earnings. In respect of indirect forex earnings duly certified by Chartered Accountant such as amount received from Travel agents/Tour Operators, Foreign Airlines for stay of Crew and Catering, UN organizations and Diplomatic Missions and Encashment Certificate from authorized dealers and others in terms of DGFT Policy circular no.60/97-2002 dated 24.12.1998

1. The financial information given in the above statement is in agreement with the relevant register and records; the same has been incorporated in the books of accounts maintained by the Service provider; and is also true and correct.
2. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect; no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld;

3. Neither I, nor any of my partners/director is a partner, director, or an employee of the above-named entity or its associated concerns;
4. I/We fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

(Signature and Stamp/ Seal of the Signatory)

(Chartered Accountant/ Cost & Works Accountant)

Place: _____ Name of the Signatory : _____
Date: _____ Full Address : _____

Membership No. : _____